एकम् सनातन भारत दल

सनातन मूल्य सर्वोपरि

लोकसभा

2024

घोषणापत्र

- ✓ एकम् के सप्त-संकल्प
- ✓ महंगाई नियंत्रित आर्थिक नीति
- ✓ आरक्षण-SC/ST ACT पर दृष्टिकोण
- ✓ शिक्षा और स्वास्थ्य नीति
- ✓ गौ आधारित अर्थ व्यवस्था - गौ माता राष्ट्र माता
- ✓ शक्तिशाली भारत के लिए समृद्ध किसान
- ✓ चुनाव सुधार
- ✓ हलाल इकॉनमी बंद - लक्ष्मीनोमिक्स आरम्भ
- ✓ सुदृढ़ परिवार - सुदृढ़ राष्ट्र
- ✓ संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन
- ✓ विदेश और रक्षा नीति
- ✓ सर्वर, डाटा और सोशल मीडिया में विदेशी गुलामी से मुक्ति
- ✓ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

लोक सभा 2024 चुनावों का बिगुल बज चुका है।

हम जम्मू कश्मीर में वर्ष 2011 से निरंतर राष्ट्रवादी समाज एवं जम्मू संभाग के व्यापक सशक्तिकरण हेतु संघर्षरत रहे हैं। फिर चाहे वो

- ✓ रसाना (कठुआ केस) का वह मामला जिसमें जम्मू के लोगों का, उनके कुलदेवताओं का, एवं हिंदू मंदिरों को बदनाम करने का षड्यंत्र रहा हो, या
- ✓ जम्मू में किया गया 25,000 करोड़ का भूमि घोटाला हो, या
- ✓ रोशनी एक्ट जैसे अनेक क़ानून एवं 14 फ़रवरी 2018 जैसे जिहादी आदेश जिनका उद्देश्य जम्मू का, यानी उत्तर भारत का, यानी पवित्र हिमालय का, यानी सनातन का इस्लामीकरण था, को ध्वस्त कराना हो, या
- ✓ सुप्रीम कोर्ट में जा कर जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक मुस्लिम समाज का ग़ैर क़ानूनी ढंग से लिया जा रहा अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करा हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को यह दर्जा दिलवाने की बात हो, या
- ✓ अनेकों अनेक भ्रष्ट मंत्रियों एवं सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए दंडित करवाने की बात हो, या
- ✓ जिहादी आतंकवाद एवं अलगाववाद से सामने से लड़ने की बात हो, या
- ✓ कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा जम्मू विरोधी नीतियों एवं षड्यंत्रों का मुँह तोड़ जवाब देने की बात हो इत्यादि,

ऐसी सब चुनौतियाँ से लड़ कर विजय पाने का गौरव हमनें प्राप्त किया है।

अब इसी संघर्ष को और मज़बूती से राष्ट्रीय-स्तर पर लड़ने के लिए समस्त देश वासिओं के सहयोग एवं साथ की आवश्यकता है।

2024 के लोक सभा चुनाव में एकम् सनातन भारत दल के प्रत्याशी देश भर से लड़ रहे हैं।

दिल्ली और कश्मीर के 1947 से आज तक चले आ रहे जिस समझौते के अन्तर्गत दिल्ली ने जम्मू संभाग को कश्मीर का ग़ुलाम बना कर रखा हुआ है उस समझौते को ध्वस्त करने हेतु क्या आप हमारा साथ देंगे?

कांग्रेस के तुष्टिकरण से ले कर भाजपा के तृप्तिकरण तक देश के लगातार हो रहे इस्लामीकरण को समाप्त कर देश की राजनीति में सनातन मूल्यों को स्थापित करने हेतु क्या आप हमारा साथ देंगे?

सनातन समाज पर सरकारी नीतियों के माध्यम से हो रहे कुठाराघात को समाप्त कर सनातन सभ्यता, संस्कृति और धर्म को राजनीति में पुनर्स्थापित करने में क्या आप हमारा साथ देंगे?

मुझे पूरा विश्वास है कि लोक सभा 2024 चुनावों में देश भर से केवल और केवल एकम् सनातन भारत दल के उम्मीदवारों को वोट देकर इस धर्मयुद्ध में आप अपनी आहुति अवश्य देंगे।

- आपका अंकुर शर्मा,
संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष।

अंकुर शर्मा

राष्ट्रीय अध्यक्ष

एकम् सनातन भारत दल

एकम् सनातन भारत दल का घोषणा पत्र आप सबके सामने है। जिस तरह से पार्टी ने सप्त संकल्प के जरिए सनातन समाज के सामने अपना स्पष्ट एजेंडा रखा, उसी तरह घोषणा पत्र के जरिए भी हमने अपना साफ दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया है।

हो सकता है हमारी कुछ घोषणाएं आपको पोलिटिकली करेक्ट न लगे, लेकिन हम पोलिटिकल करेक्ट होने भी नहीं आए हैं। हम इस राष्ट्र की मूल समस्या को समझ कर उसका समाधान प्रस्तुत करने आए हैं।

स्वतंत्रता के बाद से हमने केवल पार्टियां और नेता बदले हैं, हम व्यवस्था बदलने में नाकाम रहे हैं। और यह सब पोलिटिकली करेक्ट होने की बीमारी की उपज है। नेता और जनता, दोनों पोलिटिकल करेक्ट होना चाहते हैं, जिस कारण समस्या विकराल रूप लेती चली जा रही है।

गरीब और गरीब हो रहा है, सनातन संस्कृति और मूल्यों को जीवन से खरोंच कर अनैतिकता व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, आरक्षण का लाभ केवल आरक्षित वर्ग के सुविधा संपन्न वर्गों तक सीमित होकर रह गया है, SC/ST act न्याय पाने की जगह डराने का तंत्र बन गया है, जातिविहीनता का दावा करने वाले मजहब और रिलीजन को संविधान को ताक पर रख कर आरक्षण दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को तबाह कर दिया गया है, शिक्षा व स्वास्थ्य से सरकारें हाथ खींच रही हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता की जगह ठेके पर रखा जाने वाला मजदूर बन कर रह गया है, युवकों की बेरोजगार बढ़ती जा रही है, भारत को सर्विस सेक्टर में बदल कर अरब-अमेरिका का उपनिवेश बनाया जा रहा है, कर के मार से मध्यम वर्ग का खून चूसा जा रहा है, व्यापारी GST से कराह रहा है, गृहणियां महंगाई की मार झेल रही हैं, किसान आत्महत्या करने को विवश है, हिमालयन राज्यों का इस्लामीकरण कानूनी-गैरकानूनी रूप से कराया जा रहा है, चुनाव अरबों-खरबों का खेल बन गया है और जनता को हर पांच साल बाद वोट देने के अधिकार के अलावा अन्य सभी अधिकारियों से वंचित रखा गया है!

ऐसे में एकम् सनातन भारत दल का घोषणापत्र इन सारी समस्याओं का स्थाई समाधान लेकर जनता के बीच आया है। पांच साल का खेल बहुत हो गया, यदि वास्तव में सनातन सभ्यता-संस्कृति व भारत को बचाना है तो अब हमें व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। हम इसके लिए कृतसंकल्पित हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? एकम् का घोषणा पत्र आपसे यह सवाल पूछता है?

संदीप देव,
राष्ट्रीय महासचिव (संगठन)

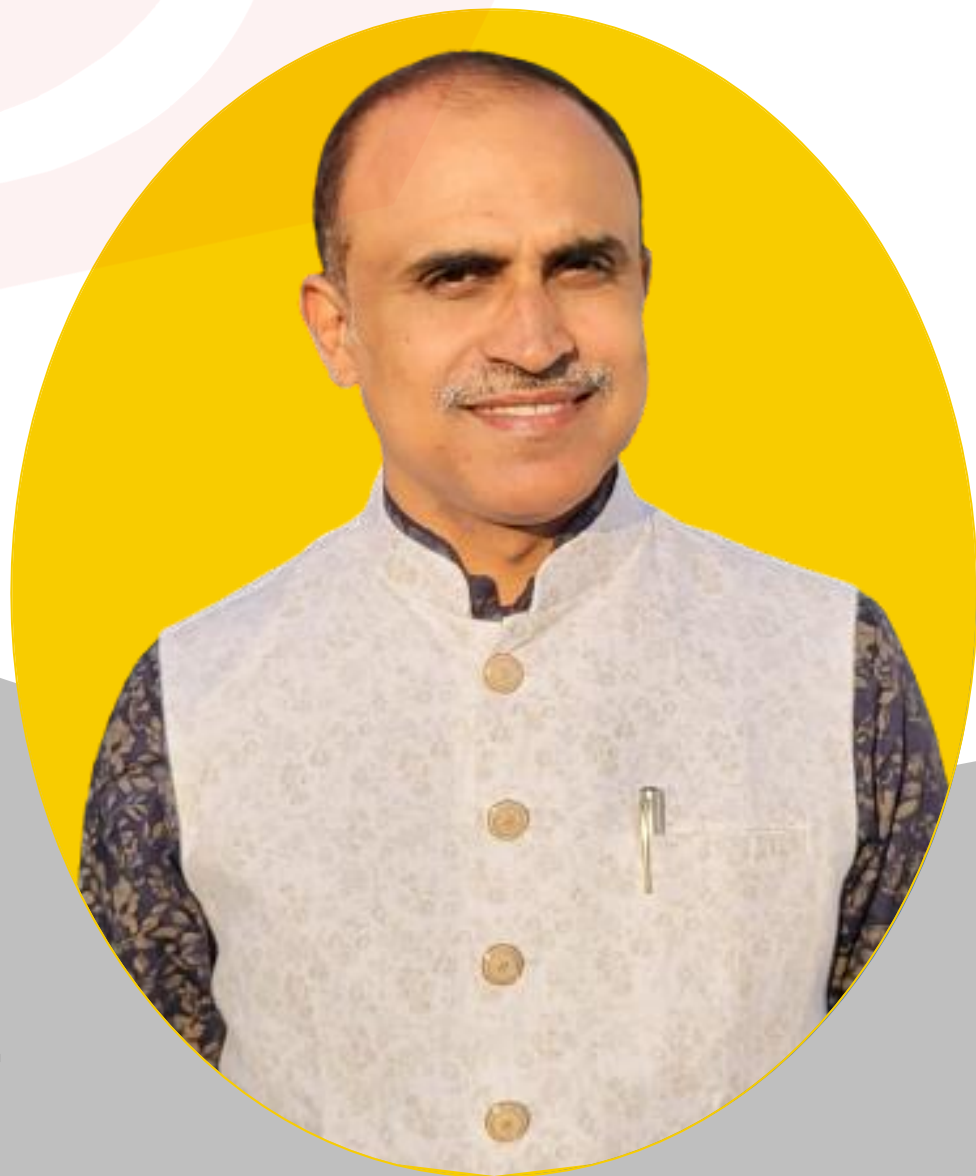

संदीप देव

राष्ट्रीय महासचिव

एकम् सनातन भारत दल

अपने सीमित संसाधन के साथ राजनीति में सनातन मूल्यों को स्थापित करने का बड़ा लक्ष्य लेकर श्री अंकुर शर्मा के नेतृत्व में बने एकम् सनातन भारत दल ने एक साल से भी कम समय में राजनीतिक विमर्श में अपनी जगह बना ली है।

पार्टी की घोषणा होने के बाद, पहले दिन से ही, भारी संख्या में लोग इस पार्टी से जुड रहे हैं। शुरुवात में एकम् से जुड़ने वाले ज्यादातर लोग बुद्धिजीवी वर्ग से ही थे जो मीडिया और सोशल मीडिया में चलाये जा रहे प्रायोजित विमर्श से प्रभावित हुए बिना सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता रखते थे। ये वही वर्ग है जो 2014 के समय नरेंद्र मोदी के पीछे मजबूती से खड़ा था, क्योंकि उस समय मोदी सच्चर कमिटी जैसी नीतियों का विरोध कर रहे थे, तब किसी ने भी नहीं सोचा था की सत्ता में आते ही मोदी उसी सच्चर कमिटी को क्रियान्वित करने में लग जाएंगे। जो कहते थे 'Justice for All – Appeasement for None!', वो मजहबी तुष्टिकरण की सारी हदें पार कर देंगे।

यही नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सत्ता में आयी मोदी सरकार, विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों के मकड़जाल में देश भर के लोगों को फसा रही है। यूरोपीय संघ, GDPR जैसे रेगुलेशन ला कर अपने लोगों को कंपनियों की डिजिटल गुलामी से बचा रहा है। जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ़्रीका, अर्जेंटीना और यहाँ तक केन्या जैसे देश भी अपने नागरिकों के हित में क़ानून बना रहे हैं। वहीं भारत में जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए GDPR जैसा कोई कानून नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार (पिछली सरकारों की ही तरह) इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां बना कर भारत को आर्थिक उपनिवेशता की तरफ तेजी से बढ़ा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के कारण Electoral Bond का जो डाटा सामने आया है वह भी सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच साठ-गांठ को उजागर करता है। चंदा देने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो सरकार नियम बना रही हो, वो देश और देशवासियों के लिए क्या काम करेगी?

आज हालत ये है की बहुत से सरकारी विभागों का काम भी WhatsApp और Gmail जैसे विदेशी प्लेटफार्म पर हो रहा है जिसका डाटा देश से बाहर होने के साथ भारत सरकार के नियंत्रण से भी बाहर है। सभी बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफार्म विदेशी हैं और देशवासियों के निजी डाटा का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए मनमाने ढंग से कर रहे हैं।

मुझे प्रसन्ता है की जब देश की सभी राजनीतिक पार्टियाँ विदेशी कंपनियों को खुश करने की होड़ में लगी हैं, तब एकम् सनातन भारत दल अपने इस घोषणापत्र के माध्यम से भविष्योन्मुखी मुद्दों को देश के समक्ष रख कर भारतीय राजनीति में सनातन मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयासरत है।

कमल रावत,
राष्ट्रीय महासचिव (प्रशासन)

कमल रावत

राष्ट्रीय महासचिव

एकम् सनातन भारत दल

राष्ट्रीय घोषणापत्र समिति

Members

- **Sh. Suresh Kumar Shukla (President)**
- Smt. Bhawana Dubey
- Smt. Meenakshi
- Smt. Manini Bajpai
- Smt. Jyoti Pandey
- Smt. Indu Upadhyay
- Sh. Jugal Kishore
- Sh. Yuvraj Singh
- Sh. Joginder Singh
- Wing Com. Pushkal Dwivedi (Ret.)
- Adv. Rachna Naidu
- Sh. Ramaker Thakur
- Sh. Rajiv Shah
- Sh. Vinod Shahi
- Sh. Hira Lal
- Sh. Ajay Handique
- Sh. Gnanesh. N
- Sh. Anand Ganesh
- Sh. Bijit Singha
- Sh. Sanjeev Yadav
- Smt. Brinda Chowdhari
- Sh. Sandeep Sharma
- Sh. Vedant Giri
- Sh. Rakesh Yadav
- Wing Com. Rakesh C. Srivastava (Ret.)
- Commander Vikram Pandey (Ret.)
- Smt. Geetanjali Tripathi
- Sh. CA Manoj
- Sh. Rajeev Kapoor
- Sh. Ravi Ranjan Singh Jhatka
- Sh. V. D. Bajaj
- Sh. Anand Ganesh
- Subroto Roy
- Vipul Rege
- Dr. Anil Sangli
- Commander Naresh
- Dr. Arun Maan
- Dr. Yogender Shokeen
- Sh. Umesh Rawat
- Sh. N. K. Vaid

प्राचीन काल से मराठा साम्राज्य तक भारत की पहचान बहुत सुदृढ़ थी। सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आक्रांता पहले भी आए थे और इसके बाद भी आते रहे। ईसाई अंग्रेजों ने संस्थागत लूट के लिए हमारे सनातन धर्म और सभ्यता को बहुत तरीकों से चोट पहुंचाई। हमारे गुरुकुल, आयुर्वेद चिकित्सा, मंदिर, न्याय प्रणाली , गांव आधारित समाज व्यवस्था आदि अनगिनत तरह से नुकसान पहुंचाया।

1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी कम्यूनिस्टों , म्लेच्छों और विधर्मियों ने इस परिस्थिति को यथावत बनाए रखा और कुछ बातों में तो और नुकसान पहुंचाया। काशी विश्वनाथ, वैष्णों देवी, जगन्नाथ पुरी, आदि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण किया गया। श्रद्धालुओं के दान को सरकार ने मनमाने तरीके से उपयोग किया।

सनातन सभ्यता संस्कृति में विश्वास करने वालों के साथ विधर्मियों व राष्ट्रद्रोहियों को जबरदस्ती एक बताने वाली संघी विचारधारा पनपी। हिंदुत्व की विचारधारा वाले संघ और उससे उपजे संगठनों ने हिंदु समाज को खूब छला। अवसरवादी पार्टियों ने देश के बहुसंख्यक समाज को धोखे में रखकर इस परिस्थिति को और बिगड़ने दिया। विदेशी शक्तियां भी इन सनातन-विरोधी गलत कार्यों में परोक्ष रूप से सहायता देती पाई गई हैं।

एकम् सनातन भारत दल की इस घोषणापत्र समिति ने सनातन मूल्यों को विशेष रूप से अपने सप्त-संकल्पों को ध्यान में रखते हुए यह घोषणापत्र बनाया है।

सनातन समाज का ऐसा रूप जो युगों से चला आ रहा है और पवित्र आदर्शों पर आधारित है। एक ऐसा समाज जहां शास्त्र दैनिक कार्यों में मार्गदर्शन करते हैं और धर्म की सभी संपद्रायों को बराबर सम्मान मिलता है।

- ✓ एक ऐसा समाज जहां सनातन मूल्यों की रक्षा सर्वोपरी है और करुणा-अहिंसा का सच्चा अर्थ भी प्रकट होता है।
- ✓ एक ऐसा समाज जहां सनातन मूल्य ही एकसूत्र में जोड़ते हों और उन्ही से ही संरक्षित हो।
- ✓ एक ऐसा समाज जो इन मूल्यों के प्रचार प्रसार में सतत लगा हो और साथ ही शोध द्वारा समाज को उर्जा, तकनीकी, विज्ञान और समाजशास्त्र में प्रगति दिलाए।
- ✓ जहाँ कर (टैक्स) ऐसे लिया जाए जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती हो।

ऐसे समाज और राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को मन में रख कर इस समिति ने ये घोषणापत्र बनाया है।

अपना मूल्यवान समय और ज्ञान देने के लिए मैं समिति के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

सुरेश शुक्ला,
अध्यक्ष, घोषणापत्र समिति।

एकम् सनातन भारत दल के सप्त संकल्प

1 एकम् सनातन भारत दल संविधान में संशोधन कर भारत की राजसत्ता को संवैधानिक तौर पर बाध्य करेगा कि वह भारत का सनातन बाहुल्य चरित्र सदा-सदा के लिए सुनिश्चित एवं संरक्षित करे।

हिंदू नरसंहार एवं जनसांख्यिकी परिवर्तन (भूमि जिहाद अथवा अन्य साधनों से) भारत की राजसत्ता के विरुद्ध किए गए अपराध माने जाएँगे जिनको ले कर मृत्युदंड का प्रावधान कानून द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

2 संविधान में संशोधन कर केवल 5% से कम जनसंख्या वाले समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देना। साथ ही भारत को विश्व के सभी सनातनधर्मियों का नैसर्गिक राष्ट्र घोषित कर उनके लिए नागरिकता का मार्ग खोलना।

3 मंदिरों और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना। मंदिरों में भगवान के अधिकार को सर्वोच्च रखना। कश्मीर स्थित भगवान भास्कर के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर, मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और काशी के ज्ञानवापी तीर्थ क्षेत्र की पुनर्स्थापना करना।

4 समस्त हिमालयी राज्यों का सनातनी स्वरूप अक्षुण्ण रखना तथा J&K का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वतंत्र राज्य बनाना।

5 भारतीय गौ-वंश की हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर शंकराचार्यों के निर्देशानुसार गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करना तथा माँ गंगा और श्री रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना।

संविधान की प्रस्तावना में असंवैधानिक रूप से जोड़े गये सेक्यूलर और समाजवाद को हटाकर राम राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखना।

6 वक्फ एक्ट, Places of Worship Act एवं सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करना। संविधान के अनुच्छेद 30 को संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार देना। समीक्षा कर सनातन संस्कृति एवं सभ्यता को हानि पहुंचाने वाले अनुच्छेद, कानून एवं धाराओं को निरस्त करना। लव जिहाद और धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाना।

7 केवल विकास नहीं, अध्यात्म, संस्कृति, सही इतिहास, सामाजिक मूल्य, क्षेत्रीय भाषा और पर्यावरण के साथ संपूर्ण विकास। भारतीय सेना के परंपरागत ढांचे को अक्षुण्ण रखना और सेना एवं पुलिस का सशक्तिकरण व आधुनिकीकरण करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को उचित सम्मान दिलाना।

01
महंगाई नियंत्रित आर्थिक नीति

मजहब, मत, पंथ के आधार पर दिया जा रहे सभी प्रकार के अनुदान तथा वजीफे (स्कालरशिप) बंद किये जाएंगे।

एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, विंडफॉल टैक्स, सरचार्ज आदि टैक्स समाप्त किये जाएंगे

300 रु में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा।

70 रु/लीटर पेट्रोल, 50 रु/लीटर डीजल। पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में ला कर इसे सस्ता करेंगे ।

12 लाख की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं होगा।

GST का सरलीकरण। 5%, 10% और अधिकतम 15% के केवल 3 स्लैब। सालाना 12 करोड़ तक के व्यापार को GST Filing से मुक्ति।

मजहब के आधार पर दी जा रही सभी सब्सिडियां तुरंत बंद होंगी।

अवैध घुसपैठियों पर सरकारी खजाना लुटाने की सभी सरकारी नीतियां तुरंत बंद की जाएंगी।

मध्य वर्ग के लिए शहरों में कम कीमत वाले फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा।

महंगाई की दर घटाकर रोजमर्रा के सामान की कीमतों को हमेशा नियंत्रण में रखा जाएगा।

ग्रामीण-स्तर पर रोजगार का जाल बिछाया जाएगा।

फार्मा लॉबी का मकड़जाल तोड़कर गैर-जरूरी दवा, टैस्ट, वक्सीन का जनता पर थोपा जाना तुरंत बंद करेंगे।

सभी निजी वाहनों का टोल टैक्स समाप्त किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे की टिकट पर मिलने वाली 50% छूट को पुनः बहाल किया जाएगा।

02
आरक्षण, SC-ST ACT पर दृष्टिकोण

1. स्वतंत्रता के बाद से अभी तक आरक्षण का लाभ आरक्षित जातियों के निचले तबके तक कितना पहुंचा है, इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
2. अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह के अनुसार, 58 जातियों और 14 जनजातियों में मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। वहीं, वर्तमान मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले के अनुसार, 80 फीसदी मुस्लिम ओबीसी में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। SC/ST तथा OBC में आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिम तथा ईसाई को तत्काल आरक्षण से बहार निकाला जाएगा।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति में मुस्लिम-ईसाई आरक्षण का रास्ता ढूंढने के लिए मोदी सरकार द्वारा बनाए गये डॉ. बालाकृष्णन कमेटी को तत्काल रद्द किया जाएगा।
4. SC/ST तथा OBC वर्ग के पहली से बारहवीं कक्षा तक लगातार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
5. किसी भी परिवार के पास 1000 वर्ग फुट से बड़ा आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज तथा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से बड़ा आवासीय भूखंड हो, तो अभी उसे केंद्र सरकार के तहत EWS आरक्षण में कोई भी लाभ प्राप्त करने से बाहर रखा गया है - इन अव्यवहारिक और अनुचित शर्तों को हटाया जाएगा।
6. विधानसभा तथा लोकसभा में आरक्षित सीट की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त की जाएगी ताकि दलितों के साथ हो रही राजनीतिक धोखाधड़ी को बंद किया जा सके।
7. प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा।
8. बिना जांच के SC/ST ACT में गिरफ्तारी पर रोक लगेगी। गलत आरोप पाए जाने पर आरोप लगाने वाले पर जुर्माने का प्रावधान होगा तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार केस में अदालत का अंतिम निर्णय आने के उपरान्त ही पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा।

03
शिक्षा और स्वास्थ्य नीति

शिक्षा और चिकित्सा में दिया जाने वाला बजट दोगुना किया जाएगा।

शिक्षा

1. सनातन वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा अनुच्छेद 30 को संशोधित कर हिंदूओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार मिलेगा।
2. मातृ भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता, उच्च शिक्षा की पढाई भी मातृ भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 10 तक संस्कृत अनिवार्य होगी।
3. NCERT की सभी पुस्तकों का पुन: निरीक्षण तथा भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन किया जाएगा।
4. संविधान में संशोधन कर पूरे देश में एक-समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी तथा मदरसा शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। कोचिग शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया जाएगा।
5. सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के स्तर की शिक्षा निशुल्क मिलेंगी।
6. लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर शिक्षक भर्ती आयोग का गठन किया जाएगा। शिक्षकों के सम्मान को राष्ट्र-निर्माता के रूप में स्थापित किया जाएगा।
7. शिक्षा में ठेका प्रणाली बंद होगी और सभी शिक्षकों को स्थायी नौकरी मिलेगी। सरकारी स्कूलों और सरकारी विश्व विद्यालयों के शिक्षा और आधारभूत संरचना के स्तर में विश्व-स्तर का बदलाव करेंगे।
8. मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढाई में डोनेशन को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा तथा उनकी पढ़ाई को मातृभाषा में प्रोत्साहित किया जाएगा।
9. मानविकी (Arts) की पढ़ाई में शोध को विश्व- स्तरीय बनाया जाएगा तथा मानविकी से मौलिक विषय पर PhD करने वालों को सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर सिविल सेवा में सीधे भर्ती किया जाएगा।
10. प्रतिभा पलायन (ब्रेन-ड्रेन) को रोकने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। सरकारी संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को दूसरे देशों में स्थानांतरित होने से पहले कम से कम 3 वर्षों तक अपने देश में ही सेवा देनी होगी।
11. भारतीय मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा उस पर शोध करने के लिए एक अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारतीय कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाएगा।

स्वास्थ्य

1. निजी अस्पताल में 25% गरीबों का निशुल्क इलाज की अनिवार्यता को सख्ती से लागू किया जाएगा।
2. सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पताल के समकक्ष खड़ा किया जाएगा।
3. आयुष्मान भारत में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। आयुष्मान भारत में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा तथा भारत के प्रत्येक परिवार को इससे जोड़ा जाएगा।
4. भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देते हुए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को विश्व-स्तरीय बनाया जाएगा। एलोपैथी के साथ सभी वैकल्पिक चिकित्सा पद्दतियों का एकीकरण किया जाएगा।
5. आर्युर्वेदि चिकित्सा पद्धति (और उसमे भी गौ आधारित औषधि) के शोध में अधिक बजट दिया जाएगा।
6. हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक चिकित्सालय खोल कर वहां स्थायी मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।
7. MBBS/MD डॉक्टरों के लिए गांव में 1 साल सेवा देना अनिवार्य होगा।
8. डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाये जाएंगे।

04

गौ आधारित अर्थ व्यवस्था

(गौ माता राष्ट्र माता)

1. भारतीय गौवंश की **हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध** लगाकर ऐसा करने वालों के लिए **मृत्युदंड का प्रावधान** लाया जाएगा।
2. शंकराचार्यों के निर्देशानुसार **गौमाता को राष्ट्रमाता** के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। भारतीय नस्ल के गौवंश के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना।
3. सभी भारतीय गौवंश का **पंजीकरण** कर उनका रिकॉर्ड रखना जिससे अवैध तस्करी पर रोक लगे।
4. गौ **मांस के आयात, निर्यात, व्यापार** आदि पर पूर्ण प्रतिबंध होगा तथा ऐसा करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान होगा।
5. गौचर भूमि पर से भूमाफियाओं और राजनेताओं के कब्ज़े को हटा कर हर **गौचर भूमि** का स्वामित्व उस स्थान की गौमाताओं को दिया जाएगा।
6. गौ रक्षकों को लोकल पुलिस थानों के साथ जोड़ कर कानूनी सहायता दी जाएगी।
7. ग्राम-स्तर पर **गोधन-केंद्र खोले जाएंगे** जहाँ सरकार ग्रामीणों से गोबर, गौमूत्र तथा जैविक रसोई एवं कृषि अपशिष्ट खरीदेगी। इससे रोजगार के नए आयाम खुलेंगे, छुट्टा पशु की समस्या समाप्त होगी और गाँव के स्तर पर जैविक खाद तथा रसोई गैस का निर्माण होगा।
   - ✓ गोधन-केंद्र से उत्पादित **गैस** को उस गाँव के हर घर में निशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था होगी। इससे हर घर को रसोई के लिए निशुल्क गैस प्राप्त होगी।
   - ✓ गोधन-केंद्र से उत्पादित **ऑर्गेनिक खाद** सस्ते दामों में उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बंजर होती जमीन को दुबारा से उपजाऊ बनाया जा सकेगा।
   - ✓ गोधन-केंद्र से उत्पादित **ईंधन** का उपयोग कर देश को अगले दस साल में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर बना कर अरब देशों पर निर्भरता को समाप्त किया जाएगा।
8. पंचायत स्तर पर पशु अस्पताल खोले जाएंगे जिसमे स्थाई पशु चिकित्सक नियुक्त किया जाएगा।

05

शक्तिशाली भारत के लिए समृद्ध किसान

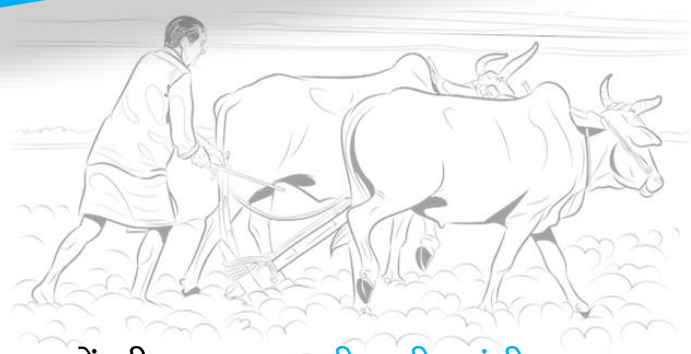

1. पूरे देश के किसानों के लिए सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव तय किये जाएंगे।
2. किसानों की पूर्ण कर्जमुक्ति की जायेगी।
3. मौसमी प्राकृतिक मार से हुए फसल के नुकसान का मुआवज़ा 90 दिनों के भीतर देने की व्यवस्था की जाएगी।
4. जैविक खाद बनाने के लिए पंचायत और ब्लाक स्तर की सहकारिता संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान रखा जाएगा। इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी।
5. सरकार द्वार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे कर अपाहिज बनाने की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। उन लोगों को हमारी सरकार द्वार गांव के स्तर पर ही कुटीर-उद्योग स्थापित कर के दिया जाएगा। उनके उत्पाद को सरकार सीधे खरीदेगी। इससे वे याचाक की जगह एक लघु उद्यमी के रूप में अपने साथ-2 अन्य लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे।
6. नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां एवं खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान लाया जाएगा।
7. गांव में सहकारिता आधारित उपक्रमों को खड़ा किया जाएगा।
8. गाँव में कृषि के साथ गैर कृषि आधारित आर्थिक इकाइयों को भी खड़ा किया जाएगा।
9. हाइब्रिड बीज खत्म कर पारंपरिक तरीके से बीज संरक्षण किया जाएगा।
10. फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
11. डब्ल्यूटीओ (WTO) की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर भारतीय किसानों के हितों के संरक्षण को सर्वोपरि रखा जाएगा।
12. गौचर भूमि को मुक्त करा कर गांव स्तर पर पंचायती खर्चे पर ग्वालों की व्यवस्था की जायेगी जिससे :
    - ✓ रोजगार निर्माण होगा।
    - ✓ पशु-धन पर हो रहा किसान का खर्चा कम होगा (दिन में पशु गौचर भूमि में रहेगा)।
    - ✓ पशु-धन स्वस्थ रहेगा (पूरा दिन खूंटे से बंधा नहीं रहेगा)।
    - ✓ पशु-धन को संभालने के लिए किसान को कम मेहनत करनी होगी।
13. ग्राम स्तर पर खेल-कूद की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे किसान के बच्चे एशियाड, ओलिंपिक आदि प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो सकें।

06 चुनाव सुधार

1. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध और असंवैधानिक घोषित किए गये इलेक्ट्रोल बांड के जरिए 2017-18 से भारतीय राजनीति में नकली और मुखौटा कंपनियों के जरिए आए कालेधन और विदेशी फंड की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

2. सभी राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग को आरटीआई (RTI) के दायरे में लाया जाएगा।

3. चंदा देने वाले शख्स और कंपनियों की पहचान सार्वजनिक की जाएगी ताकि चुनाव में पारदर्शिता आए। जनता को पता चले कि किस पार्टी को किससे व्यक्ति, संस्थान या कंपनी से चंदा मिल रहा है।

4. विदेशी चंदे पर पूरी तरह से रोक लगेगी, जो अभी विदेश की भारत में स्थित सहायक कंपनियों के जरिए सभी पार्टियां हासिल कर रही हैं। इससे देश की राजनीति और सरकार में विदेश और अंतरराष्ट्रीय लॉबिस्टों का हस्तक्षेप समाप्त होगा।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन कर कंपनियों व कारपोरेट सेक्टर को यह छूट दिया गया है कि वह अपने वार्षिक लाभ-हानि खाते में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे को छुपा सकती है। इससे राजनीतिक दल और सरकार ऐसी कंपनियों को देश व जनता की कीमत पर अनुचित लाभ प्रदान करती हैं। कंपनी अधिनियम में मोदी सरकार द्वारा किए गये इस संशोधन को समाप्त किया जाएगा और कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कंपनियां अपने वार्षिक लेखा-जोखा में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे का विवरण अनिवार्य रूप से दे।

6. छोटी पार्टियां चुनाव लड़ सकें इसलिए सरकार द्वारा ऐसी पार्टियों को लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग की जाएगी।

7. चुनाव आयोग द्वारा तय रकम से अधिक खर्चे को रोकने के लिए बड़ी पार्टियों द्वारा पांच साल में लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल सीटों से अधिक रकम चंदे में लेना अवैध बनाया जाएगा।

8. कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी सालाना पांच करोड़ से अधिक चंदा किसी भी राजनीतिक दलों को नहीं दे सकती है। इससे चुनाव में बढ़ रहे बेतहासा धन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

07

हलाल इकॉनमी बंद - लक्ष्मीनोमिक्स आरम्भ

1. भारत में हलाल सर्टिफिकेशन को पूर्ण रूप से बंद करेंगे।

2. हलाल सर्टिफिकेशन के स्थान पर हमारी सरकार लक्ष्मीनोमिक्स सर्टिफिकेशन आरंभ करेगी, जिसके बिना किसी भी उत्पाद का आयात-निर्यात और उसकी बिक्री नहीं हो सकेगी।

3. मांसाहारियों के लिए झटका-मीट का विकल्प हर जगह सुनिश्चित किया जाएगा।

4. मदरसों को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान पूर्णतः समाप्त किया जाएगा।

5. कश्मीर से निकाले गए हिन्दुओं को सुरक्षा के साथ पुनर्स्थापित करेंगे और हिन्दुओं के नरसंहार को अधिकारी रूप से नरसंहार घोषित कर यूएन कन्वेन्शन ऑन क्राइम्स अगेंस्ट जीनोसाइड के तहत नरसंहारियों (जिहादियों) को कानूनी प्रक्रिया के तेहत दंडित किया जाएगा।

6. वक्फ एक्ट, Places of Worship Act को निरस्त किया जाएगा।

7. सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन को तत्काल निरस्त किया जाएगा।

8. धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगेगा तथा इसके लिए सख्त कानून लाये जाएंगे।

9. विदेशी फंड से संचलित होने वाली देश-विरोध गतिविधियां अथवा सभी धार्मिक कृत्यों पर पूर्णता अंकुश लगाएंगे।

10. सत्ता में आने के 3 साल के भीतर बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं तथा बाकी सभी अवैध घुसपैठियों को निर्वासित कर उन्हें उनके मूल देश में भेजा जाएगा।

11. पूरे देश में NRC लागू करेंगे।

12. सभी मुख्य मंदिरों के 10 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस के प्रयोग पर रोक लगेगी।

एकम् सनातन भारत दल

08

सुदृढ़ परिवार - सुदृढ़ राष्ट्र

विवाह

1. माता-पिता की अनुमति के बिना कन्याओं को जबरन अथवा लालच दे कर अथवा झूठ बोल कर किया जा रहा अंतर-धार्मिक विवाह तथा विवाहेतर सम्बन्ध के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा। ग्रूमिंग गैंग्स को देश भर से समाप्त किया जाएगा।
2. लव-जिहाद पर कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाएगा।
3. विवाह विवाद में न्याय-प्रक्रिया में जाने से पहले मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. ऐसी समितियाँ बनायी जाएंगी जिनमें सम्मानित वरिष्ठ नागरिक, उच्च सेवानिवृत्त लोग, तथा समाज के अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। वैवाहिक विवाद के सभी मामले अदालतों में जाने से पहले इन समितियों के पास जाएंगे।
5. सनातन विवाह संस्कार पर समलैंगिकता के आक्रमण को हतोत्साहित किया जाएगा और समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जायेगी।

परिवार

1. परिवारों को संयुक्त बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जाएंगे ।
2. मृत्यु-उपरांत श्राद्ध के लिए तेरह दिनों के अवकाश को सभी संस्थानों में अनिवार्य किया जाएगा।

समानता

1. घरेलू हिंसा के कानूनों में महिलाओं के सामान ही पुरुषों को भी जोड़ कर इनको लिंग के प्रति तटस्थ (Gender-Neutral) बनाया जाएगा।
2. सरकार, न्यायालय अथवा एक्टिविस्टों द्वार परिवार तोड़ने के लिए लाये गए सेक्शन-69 जैसे प्रावधानों को समाप्त किया जाएगा।
3. चल-अचल पैतृक संपत्ति में पुरुषों के अधिकार के समान ही महिलाओं को मायका या ससुराल में से केवल एक जगह ही अधिकार दिया जाएगा।
4. महिला आयोग की तर्ज पर ही राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन किया जाएगा।

कानून

1. फिल्म, कला, OTT अथवा स्कूली पुस्तकों से व्यभिचार को बढ़ावा देने वाली तथा परिवार को तोड़ने वाली सामग्री हटाई जायेगी । ऐसी सामाग्री डालने वालों के खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा।
2. परिवार को तोड़ने वाले सभी कानूनों की समीक्षा की जायेगी:
   - ✓ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'कानूनी आतंकवाद' बतायी गयी धरा 498-ए को समाप्त किया जाएगा। शादी के समय आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं की सूची को मैरिज सर्टिफिकेट के साथ रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा।

09
संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन

1. आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए करीब 40000 हिंदू **मंदिरों का पुर्नोद्धार** किया जाएगा।
2. शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा, न्याय, पुलिस कानून, सरकारी नौकरी में **वैदिक शिक्षा की स्वीकार्यता** होगी।
3. वैज्ञानिक आधार पर बने **युधिष्ठिर सम्वत वैदिक पंचांग** को सरकार का ऑफिसियल कैलेंडर बनाया जाएगा। प्रमुख और बड़े हिंदू त्योहारों पर छुट्टी अनिवार्य की जाएगी।
4. माँ गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी आदि सभी **पवित्र नदियों** में सीवर के गंदे पानी और औद्योगिक अपशिष्टों को डालने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगेगा।
5. सनातन संस्कृति एवं सभ्यता को हानि पहुंचाने वाले **अनुच्छेद, कानून तथा धाराओं** को समीक्षा कर, उन्हें निरस्त किया जाएगा।
6. भारतीय मनीषियों द्वारा किये गए शोध और खोज को उन्ही के नाम से पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा। उनका श्रेय उन विदेशियों को नहीं दिया जाएगा जिन्होंने उनके कार्यों को चुरा कर, उसे अपने नाम से प्रकाशित किया हो।
7. भारत में किसी भी स्थान या परियोजना का नाम **विदेशी आक्रांताओं** के नाम पर नहीं होगा। एक केंद्रीय कानून ला कर ऐसी सभी स्थानों का नाम एक बार में ही उनके मौलिक नाम के आधार पर बदल दिया जाएगा।
8. तीर्थ क्षेत्रों में पंडों द्वारा सुरक्षित रखे गए सभी **सनातनी पूर्वजों के रिकॉर्ड** को मान्यता प्रदान करते हुए डिजिटाइज़ कर उसका ऑफिसियल डाटा सेंटर बनाया जाएगा जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे पंडों को सरकारी अनुदान दिया जाएगा।
9. अपने पूर्वजों के **मूल धर्म में घर वापसी** करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा।
10. सभी मंदिरों एवं तीर्थ क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में **शराब और मांस** की बिक्री तथा प्रयोग पर रोक लगेगी।
11. राष्ट्रीय मार्गों पर भारतीय मूल के उपयोगी वृक्षों (पीपल, आम, जामुन, आदि) को बड़ी मात्रा में लगाया जाएगा।
12. सिनेमा, OTT तथा टीवी पर ऐसे कंटेंट बनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो अपने कंटेंट के माध्यम से बच्चों में अच्छे संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। सनातन मूल्यों, भारतीय सेना, स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय ऋषियों, आदि की गलत छवि पेश करने वाले सभी कंटेंट को पूर्णतः हटाया जाएगा।
13. न्यू वर्ल्ड आर्डर (जहाँ बच्चों में समलेंगिकता तथा लिंग परिवर्तन जैसी चीजों को प्रोत्साहित किया जाता हो) को प्रोत्साहन देने वाले कंटेंट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
14. भारत वर्ष, सनातन एवं वैदिक सभ्यता का मूल इतिहास NCERT कोर्स में शामिल किया जाएगा।

एकम् सनातन भारत दल

10 विदेश और रक्षा नीति

पुलिस और सेना में पेंशन बहाली (एक रैंक एक पेंशन) की जायेगी।

आंतरिक सुरक्षा

1. पुलिस सुधार किये जाएंगे। पुलिस का सशस्क्तिकरण तथा आधुनिकीकरण किया जाएगा।
2. भीड़ के द्वारा किये गए संगठित और नियोजित पथराव को राष्ट्रद्रोह माना जाएगा तथा इसके लिए सख्त से सख्त दंड का प्रावधान होगा।
3. भीड़ के द्वारा सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर उस नुकसान की वसूली उनकी चल-अचल सम्पति को जब्त करके किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीयकृत कानून लाया जाएगा।
4. मजहबी हिंसा के शिकार लोगों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस के अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन किये जाएंगे।
5. CISF की तर्ज पर "धार्मिक विरासत सुरक्षा सेना" का गठन किया जाएगा जो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
6. कश्मीर से निकाले गए हिन्दुओं को सुरक्षा के साथ पुनर्स्थापित करेंगे और हिन्दुओं के नरसंहार को अधिकारी रूप से नरसंहार घोषित कर यूएन कन्वेन्शन ऑन क्राइम्स अगेंस्ट जीनोसाइड के तहत नरसंहारियों (जिहादियों) को कानूनी प्रक्रिया के तेहत दंडित किया जाएगा।

सेना

1. अग्निवीर योजना को वापस कर पुरानी व्यवस्था को बहाल करेंगे।
2. भारतीय सेना के परंपरागत ढांचे को अक्षुण्ण रखा जाएगा।
3. सेना का सशस्क्तिकरण तथा आधुनिकीकरण किया जाएगा।
4. सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को उचित सम्मान दिया जाएगा।

विदेश

1. सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार को विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में जोड़ा जाएगा।
2. विश्व के सभी सनातन धर्मियों के लिए भारत को उनका प्राकृतिक राष्ट्र घोषित कर उनके लिए नागरिकता का मार्ग खोला जाएगा।
3. भारत के बाहर बसे भारतीयों को नस्लवाद, गुटबाजी, भेदभाव आदि से हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
4. भारत देश केवल उन्ही देशों की सहायता करेगा जो सनातन मूल्यों को सम्मान देते है।
5. नेपाल के हिन्दू राष्ट्र बनने का समर्थन किया जाएगा।
6. भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए मध्य पूर्व, अफ्रीका, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और लैटिन अमेरिका में सहयोगियों को बढ़ाएंगे।

11

सर्वर, डाटा और सोशल मीडिया - विदेशी गुलामी से मुक्त !

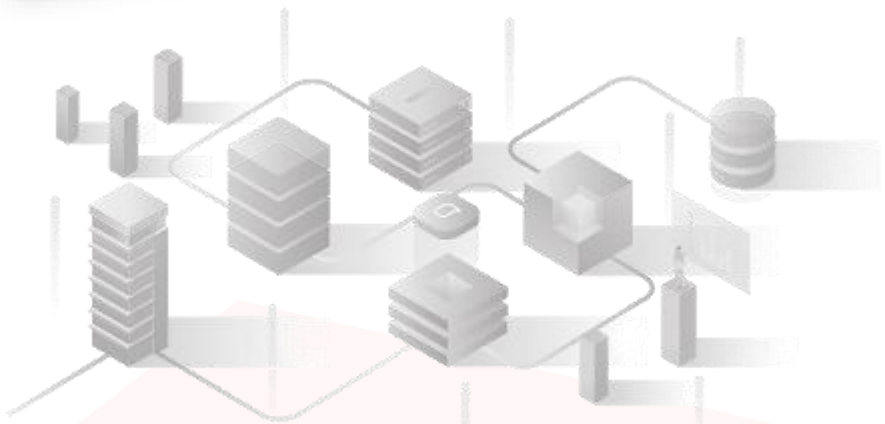

1. यूरोप के General Data Protection Regulation (GDPR) की तर्ज पर देश के लोगों के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कानून लाये जायेंगे। किसी भी कंपनी के द्वारा भारतीयों के डाटा को रखने तथा इस्तेमाल करने के तरीके में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाएगा। लोगों को अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त किया जाएगा।

2. भारत के अपने स्वदेशी विश्वस्तरीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विकसित करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे लोगों का डाटा सुरक्षित होने के साथ-2 देश में बड़े स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। इससे IT सेक्टर में हो रहा प्रतिभा पलायन भी रुकेगा।

3. लोगों के व्यक्तिगत डाटा का दुरुपयोग कर के लक्षित विज्ञापन (Targeted advertising) चलाने को रोका जाएगा। कोई भी कंपनी, किसी के भी प्राइवेट डाटा को बिना उसकी अनुमति के उपयोग नहीं कर सकेगी ।

4. PPP मॉडल पर भारत के स्वदेशी डाटा सेंटर खड़े किए जाएंगे जो भौतिक रूप से भी देश की सीमा में ही होंगे।

5. सरकार, फौज तथा उनसे जुड़े सभी कर्मचारियों का संवेदनशील डाटा और उनका व्यक्तिगत डाटा केवल देश के भीतर के डाटा सेंटरों में ही रखा जाएगा जिसे देखने का अधिकार किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होगा।

6. सरकार तथा उससे जुड़े संस्थानों के सभी कर्मचारी किसी भी विदेशी प्लेटफार्म (जैसे Gmail, WhatsApp आदि) की जगह केवल स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को ही उपयोग करेंगे।

7. AWS, गूगल क्लाउड, आदि की तर्ज पर भारत का अपना स्वदेशी पब्लिक क्लाउड बनाया जाएगा।

8. इस क्षेत्र में सालाना एक करोड़ से अधिक नौकरियों सृजित की जाएगी ।

9. सर्च इंजन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उत्पन्न नतीजों में देश तथा सनातन के विरोद में दिखाया जा रहे झूठे रिजल्ट के खिलाफ कानून लाया जाएगा।

12 अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

घोटाले

1. देश भर में सहारा के सभी निवेशकों के डूबे हुए पूरे पैसे रिफंड कराये जाएंगे। LIC बीमा धारकों की आर्थिक सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
2. शारदा चिट फंड आदि जैसी पोंजी स्कीम पर रोक लगा कर छोटे निवेशकों को लुटने से बचाया जाएगा।
3. बोफोर्स घोटाला, PM केयर फंड घोटाला, कॉफिन घोटाला, 2G घोटाला, आदि सभी घोटाले जिनके कारण सत्ता बदली और जिन्हे नई सरकार द्वारा सत्ता में आने पर दबा दिया गया, ऐसे सभी घोटालों की समय-बद्ध जांच कर उसमे सत्ता-पक्ष, विपक्ष, नौकरशाही, तथा मीडिआ की जिम्मेदारी तय की जायेगी।
4. रियल एस्टेट के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट में जिन लोगों का पैसा फसा हुआ है, उन सभी लोगों को उनका घर या पैसा एक साल के भीतर दिलाया जाएगा।

साधु-संत

1. आशाराम बापू, स्वामी नित्यानंद, बाबा राम रहीम, आदि सभी हिन्दू संतों पर चल रहे मामलों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरीय 1 साल के भीतर समाप्त कराया जाएगा।
2. हिन्दू साधु-संतों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर उन पर झूठे केस करके फसाने वाले तथा उनको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना देने वालों के खिलाफ कठोरतम दण्ड का प्रावधान लाया जाएगा।

न्यू वर्ल्डऑर्डर

1. न्यू वर्ल्ड आर्डर के हर अजेंडे (WTO, WHO, One Religion, Depopulation, बच्चों में समलैंगिकता तथा लिंग परिवर्तन जैसी चीजों को प्रोत्साहित करना, आदि) से भारतीय नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा।
2. फिल्म सेंसर बोर्ड को भारतीय मूल्यों के अनुरूप ढाला जाएगा।

खेल - कूद

1. ओलंपिक एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय खेलों में अमेरिका, रूस, चीन, और जापान स्तर की सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
2. BCCI एवं अन्य खेल संघों में बड़े पद कर केवल उस खेल को खेलने और समझने वाले खिलाड़ी ही प्रशासनिक पदों के लिए पात्रता रखेंगे।
3. राजनेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के लोगों का खेल से जुड़े विभिन्न संगठनों में दखलअंदाजी बंद कराई जाएंगी।

तीर्थ

1. पर्यटन और तीर्थाटन को अलग रखते हुए इन दोनों के लिए अलग नीतियां बनाई जाएंगी ।

एकम् सनातन भारत दल

सनातन मूल्य सर्वोपरि

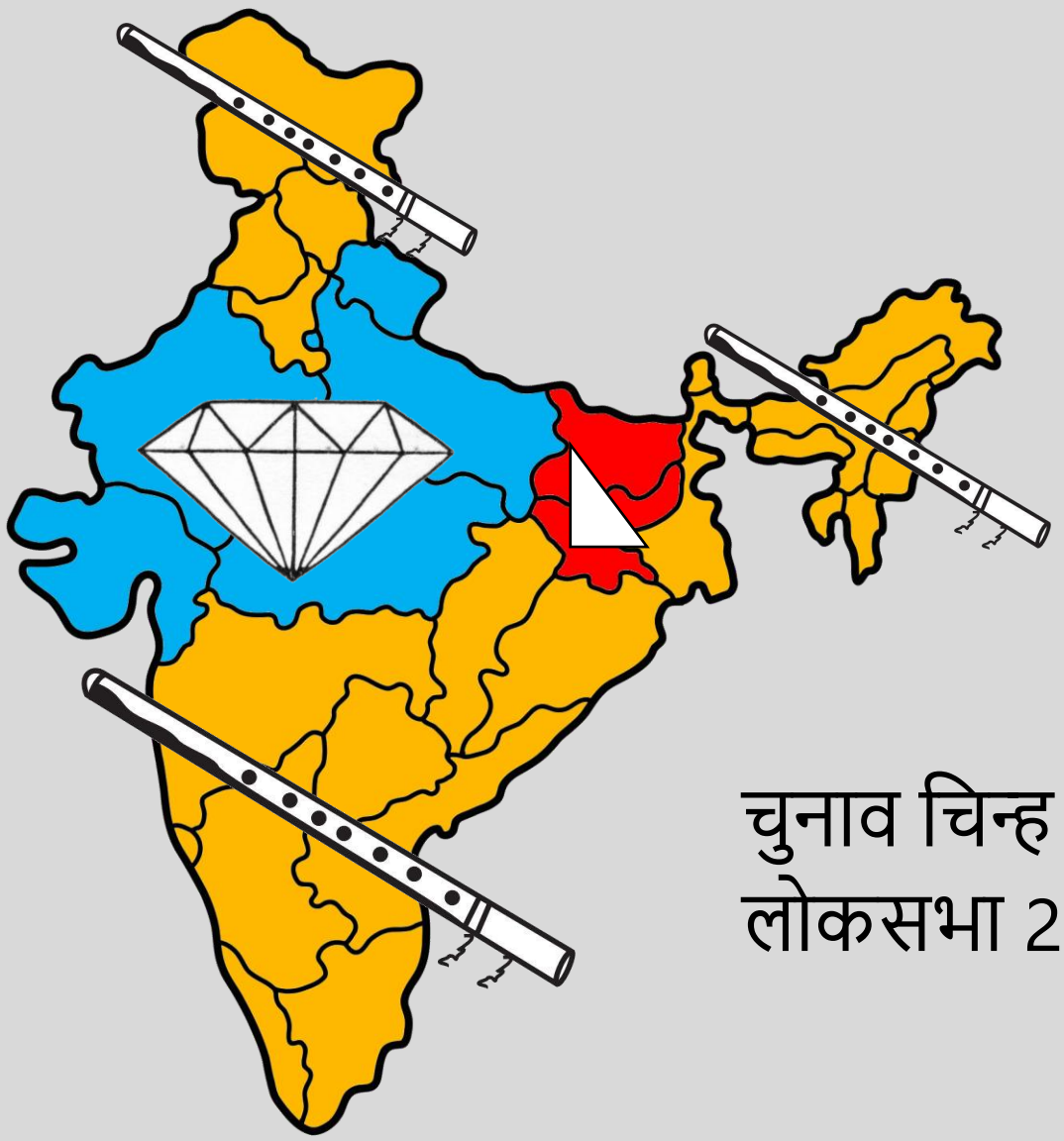

चुनाव चिन्ह
लोकसभा 2024